



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 833 राँची, बुधवार

29 अगस्त, 2018 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

29 अगस्त, 2018

विषय:- इस्लाम नगर, राँची में 444 आवास के निर्माण हेतु रु० 33,04,11,800/- (तैंतीस करोड़ चार लाख ग्यारह हजार आठ सौ रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या-1833 दिनांक: 18 मार्च, 2017 में संशोधन के संबंध में ।

संख्या: 03/न०प्र०नि०/Islamnagar-Ranchi/04/2017-4284-- आवास विहीन शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का संवैधानिक दायित्व नगर विकास एवं आवास विभाग का है । विदित हो कि इस्लाम नगर, राँची में सरकारी भूमि पर 15-20 वर्षों से अनधिकृत रूप से लोग रह रहे थे । माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन द्वारा उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था । भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के क्रम में वहाँ रहने वाले लोग विस्थापित हो गए । माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश पर उन विस्थापित लोगों को उसी जगह पर पुनर्वास करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1833 दिनांक 18 मार्च, 2017 निर्गत किया गया है ।

2. तदोपरांत उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद के “वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत

संरचना मद" से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-376 दिनांक 18 मार्च, 2017 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में राज्यांश की राशि कुल 15.00 करोड़ रुपये सर्वश्री जुडको रांची को आवंटित की गयी।

3. कालान्तर में उक्त योजना पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2017 को आयोजित 28वीं CSMC की बैठक में केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण" अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करते हुए 444 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें केन्द्रांश, राज्यांश एवं लाभुक अंशदान की राशि निम्नवत् है :-

केन्द्रांश	- 6,66,00,000.00 (प्रति आवास रु० 1,50,000/- स्वीकृत है)
राज्यांश	- 24,16,11,800.00
लाभुक अंशदान	- 2,22,00,000.00 (प्रति आवास रु० 50,000/- प्रस्तावित है)
कुल लागत राशि	- 33,04,11,800.00

4. योजना स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश राशि का प्रथम किस्त (40%) कुल 266.40 लाख रुपये आवंटित की गई है। स्वीकृत राज्यांश राशि कुल रु० 2416.1180 लाख में से पूर्व में राज्य योजना मद से 15.00 करोड़ रुपये की निकासी की गयी है तथा शेष रु० 916.118 लाख की निकासी PMAY(U) योजना के राज्यांश मद से किया जा सकता है।

5. उपर्युक्त कंडिका-3 में वर्णित केन्द्रांश की निर्गत राशि के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं० 1833 दिनांक 18 मार्च, 2017 में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं :-

कंडिका सं०	पूर्व में निर्गत प्रावधान	संशोधित प्रावधान		
कंडिका- 8	उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में राशि का वहन निम्नांकित बजट शीर्ष से किये जाने का प्रस्ताव है:- मुख्यशीर्ष-2217- शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष - 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-79- वृहद्	उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में राशि का वहन निम्नांकित बजट शीर्षों से किया जाएगा:-		
		अनुदान	बजट शीर्ष	राशि (रु०)
		केन्द्रांश	मुख्यशीर्ष-2217- शहरी विकास- उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष- 89-प्रधानमंत्री आवास योजना (पी०एम० ए०वाई०) हेतु अनुदान (केन्द्रांश)-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)-48C221780796890679	66600000

	शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)-48P221780796790679	राज्यांश	मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-79-वृहद् शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79- सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)-48P221780796790679	150000000
		राज्यांश	राज्यांश मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-89-प्रधानमंत्री आवास योजना (पी०एम०ए०वाई०) हेतु अनुदान (राज्यांश)-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान -79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)-48S221780796890679	916118000

6. इस्लाम नगर, राँची में 444 आवास के निर्माण हेतु रु० 33,04,11,800/- (तींतीस करोड़ चार लाख ग्यारह हजार आठ सौ रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या-1833 दिनांक: 18 मार्च, 2017 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

7. योजना का कार्यान्वयन विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा ।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक: 11 मार्च, 2015 के कंडिका 1.1 के आलोक में योजना पर दिनांक: 10 जुलाई, 2018 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं० - 11 के रूप में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से ।

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।
